नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 200
दि. 24.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# हॉट सीटों पर हाई वोल्टेज मुकाबला: दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, रिकॉर्ड वोटिंग ने बढ़ाई धड़कनें

देश की दो बड़ी राजनीतिक धरतियों West Bengal और Tamil Nadu में इस बार का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या पुनरावृत्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि दिग्गज नेताओं की साख, राजनीतिक भविष्य और जनसमर्थन की असली परीक्षा बन गया है। पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उन "हॉट सीटों" की हो रही है, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है और जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। रिकॉर्ड स्तर की वोटिंग ने इन सीटों के परिणामों को और भी रोमांचक बना दिया है, क्योंकि भारी मतदान को अक्सर बड़े बदलाव या मजबूत समर्थन के संकेत के रूप में देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा Suvendu Adhikari की है, जो भाजपा के प्रमुख चेहरे और नेता प्रतिपक्ष हैं। नंदीग्राम से उनकी 2021 की ऐतिहासिक जीत के बाद इस बार वे नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यहां का मुकाबला बेहद गंभीर है। उनके सामने टीएमसी के पबित्रा कर हैं, जो कभी उनके करीबी रहे हैं, ऐसे में यह मुकाबला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समीकरणों से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट पर Adhir Ranjan Chowdhury का चुनावी मैदान में उतरना इस सीट को खास बना देता है। पांच बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव हारने के

बाद अब विधानसभा में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। यहां करीब 89.60 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो यह संकेत देता है कि जनता इस मुकाबले को गंभीरता से ले रही है।

इसी तरह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Dilip Ghosh खड़गपुर सदर सीट से वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार से है। इस सीट पर भी 86 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है। वहीं जंगीपुर सीट से टीएमसी के चर्चित नेता Jakir Hossain, जिन्हें 'बीड़ी किंग' कहा जाता है, के मैदान में होने से यह सीट और भी चर्चित हो गई है, जहां लगभग 94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

पूर्व क्रिकेटर Ashok Dinda का मोयना सीट से चुनाव लड़ना भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजनीति में उनका यह नया कदम मतदाताओं के लिए दिलचस्प बना हुआ है। वहीं Nisith Pramanik और Krishna Kalyani जैसी सीटों पर भी 90 प्रतिशत से अधिक मतदान ने संकेत दिया है कि उत्तर बंगाल में भी मुकाबला बेहद कड़ा है।

तमिलनाडु में भी स्थिति कम रोचक नहीं है। यहां सबसे बड़ी नजर मुख्यमंत्री M. K. Stalin की कोलाथुर सीट पर है, जहां 83.58 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह सीट उनके राजनीतिक कद का प्रतीक मानी जाती है और यहां का परिणाम पूरे राज्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

वहीं विपक्ष के प्रमुख नेता Edappadi K. Palaniswami एदापद्दी सीट से मैदान में हैं, जहां 89 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है। यह मुकाबला सीधे तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच ताकत की तुलना के रूप में देखा जा रहा है।

तमिलनाडु के चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म अभिनेता Vijay की है, जो अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पेरम्बूर सीट से उनका चुनाव लड़ना इस सीट को हाई-प्रोफाइल बना देता है, जहां 83 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है।

इसी कड़ी में Udhayanidhi Stalin, जो मुख्यमंत्री के बेटे और द्रमुक के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी सीट से मैदान में हैं। यहां भी 81 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। भाजपा की Tamilisai Soundararajan, पूर्व मुख्यमंत्री O. Panneerselvam और केंद्रीय मंत्री L. Murugan जैसी हस्तियों की सीटों पर भी भारी मतदान ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है।

कोयंबटूर क्षेत्र में भी मुकाबला काफी चर्चित है, जहां Vanathi Srinivasan और V. Senthil Balaji जैसे बड़े नाम आमने-सामने हैं। इन सीटों पर 70 से 80 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ है, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।

इन सभी हॉट सीटों पर एक बात समान है—उच्च मतदान प्रतिशत। यह न केवल राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि यह भी संकेत है कि जनता इस बार अपने मताधिकार को लेकर बेहद जागरूक है। भारी वोटिंग का मतलब अक्सर यह होता है कि मतदाता बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त कर रहे हैं।

अब जब मतदान समाप्त हो चुका है, तो इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि कौन नेता अपनी साख बचाने में सफल होता है और किसे जनता का समर्थन नहीं मिल पाता। फिलहाल, पूरे देश की नजरें इन हॉट सीटों के परिणामों पर टिकी हैं, जो न केवल राज्यों की राजनीति को दिशा देंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक संदेश देने का काम करेंगे।

## मेघालय में सियासी बिसात पर बड़ा खेल: मुकुल संगमा पर भाजपा की नजर, बदल सकते हैं सत्ता के समीकरण

पूर्वोत्तर की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है और इस बार केंद्र में हैं Mukul Sangma, जिनके एक संभावित फैसले से Meghalaya की पूरी सियासत की दिशा बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बार फिर संगमा से संपर्क साधने की पहल की है, उसने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में राज्य में बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव है। यह मामला केवल एक नेता के दल बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव राज्य के राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकते हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता A. L. Hek ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि पार्टी मुकुल संगमा को अपने साथ जोड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा मेघालय में अपने जनाधार का विस्तार करना चाहती है और इसके लिए वह उन नेताओं से संपर्क कर रही है जिनकी पकड़ जनता के बीच मजबूत है। इस रणनीति के तहत संगमा को पार्टी में शामिल होने का न्योता देने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि संगमा ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है, बल्कि इस पर विचार करने के लिए

समय मांगा है, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना देता है।

मुकुल संगमा का राजनीतिक सफर मेघालय की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते रहे। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर All India Trinamool Congress का दामन थामा था, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। उस समय उनके इस कदम ने न केवल कांग्रेस को झटका दिया, बल्कि टीएमसी को भी मेघालय में एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब यदि वे एक बार फिर पार्टी बदलते हैं, तो यह उनके राजनीतिक जीवन का एक और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।

वर्तमान में संगमा विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय हैं और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में भाजपा का उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास यह दर्शाता है कि पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कितनी गंभीर है।

पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और अब वह इसे और विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। A. L. Hek ने यह भी दावा किया है कि केवल मुकुल संगमा ही नहीं, बल्कि राज्य के कई अन्य विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उनके अनुसार, कम से कम चार विधायक पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं और वे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस दावे ने सियासी गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो मेघालय में भाजपा को एक मजबूत राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। अभी तक राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस का प्रभाव अधिक रहा है, लेकिन भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। मुकुल संगमा जैसे बड़े और अनुभवी नेता का पार्टी में शामिल होना इस प्रयास को नई दिशा दे सकता है और पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

दूसरी ओर, All India Trinamool Congress के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। संगमा पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं और उनकी मौजूदगी ही मेघालय में टीएमसी की पहचान को मजबूत बनाती है। यदि वे पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका सीधा असर टीएमसी की संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक प्रभाव पर पड़ सकता है। इससे राज्य में विपक्ष की स्थिति भी कमजोर हो सकती है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगमा फिलहाल जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के मूड में नहीं हैं। वे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा।

## सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी: अमित जोगी की सजा पर रोक से फिर गरमाया 2003 हत्याकांड

नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति और देश की न्यायिक प्रक्रिया को एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया है। Supreme Court of India ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के पुत्र Amit Jogi को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह राहत अंतरिम है, लेकिन इसका असर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक हलकों में भी साफ देखा जा रहा है।

यह मामला वर्ष 2003 के बहुचर्चित हत्या कांड से जुड़ा है, जिसमें Ramavatar Jaggi, जो Nationalist Congress Party के नेता थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय राज्य की राजनीति में इस घटना ने भारी हलचल मचा दी थी, क्योंकि उस दौर में Ajit Jogi मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे और उनके परिवार का नाम इस मामले से जुड़ गया था।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta और Justice Vijay Bishnoi की पीठ के समक्ष हुई। अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Vivek Tankha

और Kapil Sibal ने जोरदार पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि आत्मसमर्पण की समयसीमा से राहत दी जाए, क्योंकि मामला अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

दूसरी ओर, पीड़ित पक्ष की तरफ से Siddharth Luthra और Gopal Sankaranarayanan ने सख्त विरोध दर्ज कराया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और मामले में Central Bureau of Investigation को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह पूरा घटनाक्रम उस फैसले के खिलाफ आया है, जिसमें Chhattisgarh High Court ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के पुराने फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों ही क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी थी।

हालांकि, इससे पहले 31 मई 2007 को ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि इसी मामले में अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ Central Bureau of Investigation ने अपील दायर की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई शुरू की और अंततः बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद यह साफ हो गया है कि मामला अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। यह अंतरिम राहत केवल अस्थायी है, जिसका मतलब यह नहीं है कि आरोप समाप्त हो गए हैं, बल्कि यह केवल अंतिम निर्णय आने तक की स्थिति को स्थिर रखने का कदम है।

इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि उच्च न्यायालय का फैसला कायम रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। साथ ही, Central Bureau of Investigation की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि अदालत ने उससे इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि यह एक ऐसे परिवार से जुड़ा है, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में इस केस का परिणाम केवल एक कानूनी फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, अमित जोगी को मिली इस राहत ने उन्हें तत्काल जेल जाने से बचा लिया है, लेकिन उनकी कानूनी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है।

## ट्रंप का यू-टर्न: 'नरक का द्वार' से 'महान देश' तक, बयानबाज़ी ने खड़ी की कूटनीतिक हलचल

वाशिंगटन से उठे एक बयान ने कुछ ही घंटों में वैश्विक राजनीति का रुख बदल दिया और फिर उतनी ही तेजी से उसका पलटवार भी देखने को मिला। Donald Trump द्वारा भारत को लेकर की गई विवादित टिप्पणी और उसके बाद अचानक बदले रुख ने न केवल अमेरिका-भारत संबंधों पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दिखाया कि आज के दौर में एक नेता के शब्द कितनी दूर तक असर डाल सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम महज एक बयानबाज़ी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक रणनीति और वैश्विक दबाव के जटिल मेल का उदाहरण बनकर सामने आया है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब Donald Trump ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक वीडियो और उससे जुड़ा पत्र साझा किया। यह सामग्री अमेरिकी रेडियो होस्ट Michael Savage के पॉडकास्ट से संबंधित थी, जिसमें अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता नीति पर तीखा हमला किया गया था। इस पत्र में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को "नरक का द्वार" जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, जिससे विवाद भड़क उठा। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि इन देशों के लोग अमेरिका में केवल अपने बच्चों को जन्म देकर नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं, जो कि एक संवेदनशील और विवादास्पद दावा है।

इस बयान के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश के

लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न केवल अपमानजनक माना गया, बल्कि इसे नस्लवादी दृष्टिकोण का भी उदाहरण बताया गया। भारत में राजनीतिक दलों, कूटनीतिक हलकों और आम जनता के बीच इस बयान को लेकर तीखी नाराजगी देखने को मिली। कई विशेषज्ञों ने इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिए नुकसानदायक बताया, जो पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के आधार पर मजबूत हुए हैं।

हालांकि, विवाद के बढ़ते ही Donald Trump ने तेजी से स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपना रुख पूरी तरह बदल दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता Christopher Elms के अनुसार, ट्रंप ने अब भारत को एक "महान देश" बताया और वहां के नेतृत्व को अपना "बहुत अच्छा दोस्त" कहा। यह बयान पहले दिए गए शब्दों से बिल्कुल विपरीत था, जिससे साफ जाहिर हुआ कि यह बदलाव दबाव में लिया गया एक रणनीतिक फैसला है।

इस पूरे विवाद का केंद्र अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता नीति रही है, जिसका ट्रंप और उनके समर्थक लंबे समय से विरोध करते आए हैं। इस नीति के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को स्वतः नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के हों। ट्रंप का मानना है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कई कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञ इस दावे को अतिरंजित मानते हैं और इसे आप्रवासन के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताते हैं।

विवादित पत्र में एक और मुद्दा उठाया गया, जिसमें कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारतीयों और चीनियों की भागीदारी को नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश की गई। यह दावा भी बिना किसी ठोस प्रमाण के किया गया, जिससे आलोचना और तेज हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय पेशेवरों की वैश्विक सफलता को इस तरह के बयान से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि यह उनकी मेहनत और योगदान को कमतर आंकने जैसा है।

इस बयान का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य देशों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। खासतौर पर Iran ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया और ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया। यह समर्थन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान को स्वीकार नहीं किया गया।

भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। हालांकि, आधिकारिक बयान संतुलित भाषा में दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट था कि भारत इस तरह की टिप्पणियों को हल्के में नहीं लेता। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्र हैं, और इस तरह के बयान इन संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Donald Trump का यह यू-टर्न केवल एक व्यक्तिगत बयान का बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वैश्विक आलोचना, कूटनीतिक दबाव और भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार के साथ संबंधों को बनाए रखने की जरूरत ने उन्हें अपने शब्दों को बदलने के लिए मजबूर किया। यह भी माना जा रहा है कि इस तरह के बयान कभी-कभी घरेलू राजनीति को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय असर कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है।

यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी बयान सीमित दायरे में नहीं रहता। सोशल मीडिया के जरिए वह तुरंत वैश्विक मंच पर पहुंच जाता है और उसके प्रभाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नेताओं के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें।

## संपादकीय

# लू के थपेड़ों से जन जीवन पर तपिश

एक वैश्विक संस्था एक्यूआई.इन के हालिया आंकड़ों से यह परेशान करने वाली तस्वीर उभरी है कि दुनिया के सबसे गर्म बीस शहरों में 19 भारत के हैं। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान का मुख्य कारक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकारों व आम नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में है। घटता वनों का दायरा और हमारी जीवनशैली में बदलाव से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ते तापमान का एक कारक बन रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों तक बारिश के बाद लोग अप्रैल माह में भी ठंड का अनुभव कर रहे थे। उसके कुछ ही दिन बाद तुरंत लू चलने लगी। यह अचानक होने वाला मौसमी बदलाव हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। तमाम लोग अचानक मौसमी बदलाव से उत्पन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का सबसे ज्यादा 44.4 तापमान दर्ज किया जाना गंभीर स्थिति को दर्शाता है। चिंता की बात यह है कि गर्मी सामान्य सीमाओं को पार करके आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग चेता रहा है कि देश के कई इलाकों में आगामी दिनों में लू की स्थिति बनी रहेगी। कई जगह पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। दरअसल, मौसम विभाग का मानक है कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो इसे लू चलना कहा जाता है। फिक्र की बात यह है कि अप्रैल के चौथे सप्ताह में ही देश के कई शहर हीटवेव की सीमा से आगे बढ़ गए हैं। देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्य इस तपिश का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पहली बार मध्यप्रदेश में रात को हीटवेव चलने की चेतावनी दी गई है। गर्मी का आलम यह है कि देश के कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली के स्कूलों में एक समय अवधि घंटी बजाकर छात्रों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि वे पानी पीकर गर्मी की चुनौती का मुकाबला करें।

गर्मी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देश के तमाम राज्यों में जीवन रक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। कई जगह श्रमिकों के दिन में कुछ घंटों में काम करने पर रोक लगायी गई है। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का समय बदला गया है। तमाम शहरों में लू के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कई जगह ट्रैफिक सिग्नल बंद किए गए ताकि लोगों को चौराहों पर धूप में खड़ा न रहना पड़े। सड़कों, बस स्टेशनों तथा रेलवे स्टेशनों में पानी की फुहार के जरिये गर्मी से राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताजमहल देखने पहुंचे कई पर्यटकों के बेहोश होने के समाचार हैं। गर्मी के चलते राजस्थान के कई पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में गिरावट के संकेत हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस सप्ताह दिल्ली में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। बहरहाल, इन तमाम चिंताओं के बीच प्रश्न यह है कि अप्रत्याशित गर्मी क्यों बढ़ रही है। दरअसल, अप्रैल माह में प्री-मानसून हीट पीरियड के चलते जमीन पर पड़ने वाली तेज धूप गर्मी का एक कारण है। बताया जाता है कि हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फबारी भी गर्मी बढ़ने का एक कारक है। वहीं समुद्री सतह के गर्म होने से भी गर्मी का असर तेज हो रहा है। फलतः वातावरण में ठंडक लाने वाली हवाएं व सिस्टम कमजोर होने से, वे ही गर्मी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं शुष्क हवाएं बादल बनने में अवरोध पैदा करके बारिश की संभावना को कम कर दे रही हैं। निश्चित रूप से यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भी देन है। यह वर्तमान ही नहीं, भविष्य में भी और तापमान बढ़ने की चिंता भी दर्शाता है। आशंका है कि भविष्य में तापमान में तीव्रता और बार-बार हीटवेव चलने की स्थिति बढ़ सकती है। हाल-फिलहाल मानसून से पहले की फुहारों के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्दी बारिश न होने से इस माह के बाकी दिनों में भी हमें गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

# कांशी राम की विरासत हासिल करने की जुगत

> "राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस ने पहले बेहतर काम किया होता तो कांशी राम को अलग से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की पूर्व की कुछ कमियां रही थीं जिसके कारण कांशी राम को अलग से संघर्ष करना पड़ा।

पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम को 'सामाजिक न्याय का योद्धा' और 'सशक्तीकरण का प्रतीक' बताते हुए उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' दिए जाने की मांग की। इस आशय का एक पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा। यह मांग राहुल गांधी ने लखनऊ में 15 मार्च, 2026 को कांशी राम के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए की। राहुल गांधी ने उनकी विचारधारा की प्रशंसा की और कांग्रेस की पिछली गलतियों को स्वीकार करते हुए उनके संघर्ष को याद किया। इतना ही नहीं राहुल गांधी ने कांशी राम को एक ऐसे नेता के तौर पर स्मरण किया जिन्होंने दलितों और हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। यहां तक तो ठीक है लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर कि अगर नेहरू जी जीवित होते तो कांशी राम कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते, उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया है।

उधर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के इस कदम को दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कांशी राम का सम्मान नहीं किया। इस कदम को 2027 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दलित मतदाताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस इस कदम के जरिये दलित वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने पूछा कि जब कांशी राम का निधन हुआ था तब कांग्रेस ने एक दिन का शोक तक नहीं मनाया था और वह अब किस मुंह से उन्हें 'भारत रत्न' देने की मांग कर रही है। मायावती ने राहुल गांधी के इस कदम को



दलितों के प्रति कांग्रेस का दिखावा बताया और कांशी राम की विरासत को हथियाने का प्रयास करार दिया।

राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस ने पहले बेहतर काम किया होता तो कांशी राम को अलग से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की पूर्व की कुछ कमियां रही थीं जिसके कारण कांशी राम को अलग से संघर्ष करना पड़ा। राहुल गांधी आज स्वीकार करते हैं कि वह कांशी राम के विचारों और सिद्धांतों को सही मायने में समझते हैं और इसीलिए वह लोकसभा के भीतर और बाहर भी दलितों, शोषितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों के अधिकारों जैसे मुद्दे खूब उठाते रहते हैं। संभव है वह यह साबित करना चाहते हों कि कांशी राम के विचारों और सिद्धांतों को सही मायने में वही समझते हैं और इन वर्गों की बदहाली का मुद्दा उठाते रहते हैं। राहुल गांधी का यह मानना है कि वह बसपा को हड़पने का कोई इरादा नहीं रखते बल्कि कांशी राम की सोच और विचारधारा का विस्तार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा के नतीजे इसका स्पष्ट संकेत देते हैं। दलितों, शोषितों और पिछड़ा वर्ग ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को तरजीह दी थी। जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कभी बसपा के लोकसभा में 14 सांसद थे। यह बात 1999 की है, तब बसपा के सुप्रीमो कांशी राम थे।

कांशी राम से मेरी बीसियों मुलकातें हैं। उनके जुनून को मैंने नज़दीक से देखा है। उन्हें दिल्ली के रेहगड़पुरा (करोलबाग के पास) एक छोटे से कमरे में भी देखा है और हुमायूं रोड वाले सांसदों के बंगले में देखा। उनके रहन-सहन में कोई फर्क नहीं दिखा। वह जैसे सीधे-साधे, साफगो इंसान पहले थे, यहां भी वैसे ही दिखे। फिर कांशी राम को 1971 में अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों से बने संगठन 'बामसेफ', 1981 में दलित, शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएस4) के निर्माण करते देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी संस्थाएं न तो धार्मिक हैं और न ही राजनीतिक और न ही हमारा उद्देश्य आंदोलन करना है बल्कि हमारा यह सामाजिक संगठन है। उस समय उनका नारा था—'ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया छोड़, बाकी सब डीएस4'। इसके माध्यम से दलितों, शोषितों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच चेतना जगाई और उनकी सहायता से जगह जगह छितरे मतों का एकीकरण करने का काम किया। अभी तक ये सभी मत थोक भाव से कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के बीच विभाजित हो जाया करते थे। लिहाज़ा 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना की और नारा दिया 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी'। 1984 में निर्मित बसपा के संस्थापक कांशी राम छत्तीसगढ़ के जांजगीर से लोकसभा के चुनावी मैदान में कूदे और हार गए। 1988 और 1989 का चुनाव हारने के बाद कांशी राम ने कहा था कि 'बसपा पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा नज़र में आने के लिए और तीसरा जीत दर्ज करने के लिए लड़ती है।' कांशी राम 1991 में इटावा और 1996 में होशियारपुर से लोकसभा के चुनाव जीते और 1998-2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इन चुनाव परिणामों से राजनीति में बसपा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। अब पार्टी के लोग कांशी राम को 'मान्यवर', 'साहब कांशी राम', 'बहुजन नायक कांशी राम' आदि से संबोधित करने लगे थे। इसी प्रकार मायावती ने 1989 में बिजनौर से भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीत कर बसपा की धाक जमा दी। लेकिन कांशी राम ने मायावती का कार्य क्षेत्र उत्तरप्रदेश तक ही सीमित रखा। लिहाज़ा 1995 में उन्होंने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और वह चार बार राज्य की मुख्यमंत्री रहीं 1995, 1997, 2002-2003 तथा 2007-2012 तक। पहली तीन बार वह भाजपा के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रहीं जबकि 2007-2012 तक शुद्ध बसपा की बदौलत। तीन बार सांसद होने के बावजूद कांशी राम का मन संसद में नहीं रमता था और सांसद के तौर पर उनका योगदान अधिक नहीं रहा। उन्होंने मुझे बड़ी बेबाकी से बताया था कि 'यहां बैठकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है पार्टी संगठन को मज़बूत करना।' कांशी राम अक्सर कहते थे कि हम लोग देश की आबादी का 70 फीसदी से ज्यादा हैं। हमारा शोषण ये तथाकथित बड़ी पार्टियां कई दशकों से करती आ रही हैं। उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वे कहते थे मैं अपने 'हक़ की अलख' जगाये रखने के लिए उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता रहता हूं। बेशक उनके जुनून और परिश्रम ने बसपा को मज़बूत कर दिया लेकिन उनकी सेहत की कीमत पर। उन्होंने सितम्बर, 2003 को पार्टी की बागडोर मायावती को सौंप दी। 9 अक्तूबर, 2006 को 72 साल की उम्र में कांशी राम का निधन हो गया।

कांशी राम के निधन के बाद बसपा में एकजुटता का अभाव ही दिखाई दिया। 2019 में उत्तरप्रदेश विधानसभा में 19.3 प्रतिशत मत प्राप्त कर दूसरी बड़ी पार्टी थी जबकि 2022 में खिसक कर चौथे स्थान पर आ गयी और उसके मतों की संख्या सिकुड़ कर 12.88 फीसदी रह गयी। 2007 में विधानसभा में 206 सीटें थीं जो 2012 में घटकर 80 रह गयी। उसके बाद तो बसपा पतनोमुखी ही होती चली गयी। 2017 में उसकी 19 सीटें थीं तो 2022 में मात्र एक उमाशंकर सिंह के रूप में। चुनावी विश्लेषक जानें लेकिन उसकी कमज़ोर होती कड़ी का लाभ कांग्रेस नेता राहुल गांधी खूब उठा रहे हैं। वे आज की राजनीति में कांशी राम का 'विकल्प' बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी वजह वर्तमान बसपा नेतृत्व को खोजनी होगी।

## प्रेरणा

# कर्तव्य ही असली पहचान है

Immanuel Kant जर्मनी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे। वे अपने अनुशासन, समयबद्धता और कर्तव्यनिष्ठ जीवन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके जीवन का हर क्षण एक सिद्धांत के अनुसार चलता था, और यही कारण था कि लोग उन्हें केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखते थे। एक दिन की घटना उनके जीवन के इसी मूल सिद्धांत को बहुत गहराई से प्रकट करती है।

एक सर्द सुबह थी। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही थी और चारों ओर सफेदी ही सफेदी छाई हुई थी। रास्ते लगभग बंद हो चुके थे और ठंड इतनी अधिक थी कि घर से बाहर निकलना भी कठिन लग रहा था। ऐसे में उनके नौकर ने उनसे विनम्रता से कहा कि आज कॉलेज जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम में कोई भी छात्र कक्षा में आने की संभावना नहीं है। नौकर का सुझाव व्यावहारिक था, क्योंकि परिस्थितियाँ वास्तव में प्रतिकूल थीं। लेकिन प्रोफेसर कांट ने उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद शांत स्वर में कहा कि चाहे कोई आए या न आए, उनका कर्तव्य कॉलेज जाकर पढ़ाना है। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि सामने कितने लोग हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण था कि वे अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करें। उन्होंने अपनी दिनचर्या के अनुसार तैयारी की और कठिन मौसम के बावजूद कॉलेज के लिए निकल पड़े।

जब वे कॉलेज पहुंचे, तो वहां सचमुच कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था। कक्षा खाली थी, चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन उन्होंने निराशा या खिन्नता महसूस नहीं की। उन्होंने कुछ समय वहां बिताया, जैसे कि वे हर दिन बिताते थे, और फिर शांत मन से वापस लौट आए। उनके लिए यह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही था, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा लिया था। घर लौटने पर नौकर ने मुस्कराते हुए कहा कि उसने पहले ही बताया था कि आज जाना व्यर्थ रहेगा। इस पर कांट ने बहुत ही गहन और प्रेरणादायक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही आज कोई छात्र नहीं आया, लेकिन उनका वहां जाना व्यर्थ नहीं था। उनका मानना था कि कर्तव्य का पालन केवल परिणाम के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को यह पता चले कि इतने खराब मौसम में भी उनका शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति इतना ईमानदार है, तो यह उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा।

इस छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। आज के समय में लोग अक्सर अपने कार्यों को परिणाम और लाभ के आधार पर आंकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि किसी कार्य से तुरंत फायदा नहीं होगा, तो वे उसे करने से बचते हैं। लेकिन कांट का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए कर्तव्य सर्वोपरि था, और उसका पालन करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था।

कर्तव्यनिष्ठ आचरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। यह न केवल व्यक्ति को अनुशासित बनाता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, तो वह धीरे-धीरे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उसका आचरण समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है और लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

कांट के इस विचार का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो वह देश स्वतः ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। चाहे वह एक शिक्षक हो, एक डॉक्टर हो, एक कर्मचारी हो या एक नेता—हर व्यक्ति का कर्तव्यनिष्ठ होना समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक है।

आज के आधुनिक युग में, जहां प्रतिस्पर्धा और भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहां कर्तव्यनिष्ठा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। लोग अक्सर अपने लाभ के लिए अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास प्रभावित होता है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में कांट जैसे विचारकों की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि कर्तव्य का पालन केवल बाहरी दबाव या नियमों के कारण नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली नैतिक भावना के कारण होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करता है और उसे पूरे मन से निभाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल और सम्मानित बनता है।

कांट का यह उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे घबराकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना सही नहीं है। बल्कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारे चरित्र की असली परीक्षा होती है।

अंततः, कर्तव्यनिष्ठ आचरण केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे।

# ब्रिगेड मैदान की जंग में ममता बनाम अमित शाह की जंग

प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलकाता की यात्रा की थी। उस दौरे पर उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री के कालीघाट स्थित घर का दौरा किया था। तब उन्होंने मंत्री की मां से उलाहना दिया था, आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान करती हैं। कहना न होगा कि वह शख्सियत डेढ़ दशक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी लड़ाका है। धूल से उठकर राजनीतिक आसमान का तारा अगर वे बनी हुई हैं, उसकी वजह उनका सघर्षशील व्यक्तित्व ही है। लेकिन कोलकाता के मैदान में इस बार यह योद्धा फंसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उनसे दो-दो हाथ कर रही है, निश्चित तौर पर उसके पीछे नरेंद्र मोदी की अगुआई में बंगाल की धूल में लगातार परिश्रम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज अगर बंगाली की सियासी लड़ाई आर-पार के दौर में आ चुकी है तो इसके पीछे अमित शाह की रणनीति काम कर रही है।साल 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कहा गया था कि बीजेपी चुनाव जीतते-जीतते हार गई है। ममता का संघर्ष बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ गया था। पांच साल बाद कोलकाता के रायटर्स बिल्डिंग पर कब्जे को लेकर सेनाएं सज गई हैं। लेकिन इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं। इसकी वजह अमित शाह का चुनाव प्रचार की कमान खुद संभालना है, जिन्होंने 170 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ने के बावजूद अमित शाह ने राज्य की यात्राएं जारी रखीं और इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बनाए रखा। इस बार बीजेपी अगर सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है तो इसकी बड़ी वजह बूथ प्रबंधन तो है ही, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना भी है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वह जो आज सोचता है, पूरा देश उस पर बाद में आगे बढ़ता है। शक्ति पूजा की संस्कृति वाले राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता के राज में कई बार सवाल उठे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डाक्टर से दुष्कर्म और बर्बर हत्या के बाद अंग्रेजों की पहली राजधानी का भद्रलोक उद्वेलित हो उठा। अभी इसकी आंच ठंडी पड़ी नहीं कि कस्बा लॉ कालेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुई। इसके पहले संदेशखाली में हुई कथित तौर पर यौन हिंसा और ज़मीन हड़पने के मामलों से पश्चिम बंगाल का समाज उद्वेलित रहा। अमित शाह के बार-बार के बंगाल दौरे के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मसले को कभी धीमा नहीं पड़ने दिया। इन्हीं वजहों से महिला सुरक्षा को लेकर तृणमूल कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट भी राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ही तसदीक करती है, जिसके अनुसार, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,691 मामले दर्ज किए गए और एसिड हमलों में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा करीब 27.5 प्रतिशत रहा। बीजेपी को महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने में ममता बनर्जी के एक बयान से भी मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शाम सात बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। बीजेपी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आरजी कर की पीड़िता की मां मंजू देवनाथ को पनियाहाटा से उम्मीदवार बनाकर एक तरह से राज्य की महिलाओं को संदेश दे दिया है, संदेश यह कि वह उनकी सुरक्षा के लिए संजीदा है। बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाने और नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही महिलाओं को मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह प्रतिमाह तीन हजार रूपए देने का वादा किया है। यहां याद रखना चाहिए कि ममता सरकार हर महीने महिलाओं को डेढ़ हजार रूपए दे रही है। साल 2021 में राज्य में तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें और करीब 44 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38 प्रतिशत वोट के साथ 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले देखें तो पार्टी ने तीन सीट और करीब 28 प्रतिशत वोट की तुलना में बड़ी छलांग लगाई। अमित शाह ने इसी बुनियाद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। इसके तहत उन्होंने दो बातों पर जोर दिया। उन्होंने उन गढ़ों को और मज़बूत बनाने की रणनीति बनाई, जहां पहले से ही पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही उन चुनाव क्षेत्रों में आधार बढ़ाने की कोशिश तेज की, जहां 2021 में वह बहुत कम अंतर से हारी थी। इसके साथ ही अमित शाह ने पार्टी के भीतर की गुटबाज़ी को भी सुलझाने की कोशिश की। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष के बारे में माना जा रहा था कि वे नाखुश हैं। अमित शाह ने उनसे मुलाकात करके तृणमूल से आए शुभेंदु अधिकारी से बीच उनके मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। oममता बनर्जी ने पिछली बार बंगाली माटी और मानुष यानी स्थानीय को मुद्दा बनाया था। उन्हें इस मुद्दे से पिछली बार मदद भी मिली। इस बार भी ममता विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं के बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं। इसके जवाब स्वरूप अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री 'धरती का बेटा' यानी स्थानीय व्यक्ति ही बनेगा। पार्टी ने इस बार घुसपैठ को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। राज्य में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान राज्य में नब्बे लाख वोटरों के नाम हटाने को लेकर ना सिर्फ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत समूचा गैर बीजेपी दल मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि अमित शाह चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के कदम को सही बताया है। बीजेपी यहीं नहीं रूकी है, उसने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो राज्य से अवैध घुसपैठियों की पहचान करेगी और उन्हें बाहर करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने सत्ता में आने के पैंतालीस दिनों के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार को जमीन देगी। बीजेपी ने इसके जरिए बांग्लादेश की ओर हो रही पशु तस्करी को रोकने का भी ऐलान किया है। राज्य में भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी कामयाब रही है।

## अभियान

# भोर का अनुशासन: क्यों कहते हैं बड़े कि जो सूरज से पहले उठता है, वही आगे बढ़ता है

भारतीय घरों में पीढ़ियों से एक आवाज़ गूंजती रही है—"जल्दी उठो, तभी जीवन बनेगा।" यह कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि अनुभव, परंपरा और गहरी समझ से निकला जीवन का सूत्र है। जब दादी-नानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करती हैं, तो उसके पीछे केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि शरीर, मन और जीवन के संतुलन की एक संपूर्ण व्यवस्था छिपी होती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है, जो सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले आता है। आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच माना जाता है। इस काल को दिन का सबसे शांत, शुद्ध और ऊर्जा से भरा हुआ समय कहा गया है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वज इसे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते आए हैं।

प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेष रूप से Ayurveda, इस समय को स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानती है। आयुर्वेद के अनुसार, यह समय शरीर में हल्केपन और गतिशीलता का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति इस समय उठता है, तो उसका शरीर और मन दोनों स्वाभाविक रूप से ताजगी महसूस करते हैं। यह वह समय होता है, जब रात की गहरी नींद के बाद मस्तिष्क पूरी तरह से विश्राम पा चुका होता है और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि पुराने समय में विद्यार्थी और साधक इस समय को पढ़ाई, ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे।

ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण अपने आप में अनोखा होता है। उस समय चारों ओर एक गहरी शांति होती है, जो मन को स्थिर करने में सहायक होती है। दिन के अन्य समय में जहां शोर-शराबा और भागदौड़ होती है, वहीं इस समय प्रकृति एकदम शांत और संतुलित रहती है। यह शांति मन को भीतर की ओर ले जाने में मदद करती है। जब व्यक्ति इस समय ध्यान या योग करता है, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। मानसिक तनाव, जो आज के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, इस समय किए गए अभ्यास से काफी हद तक कम हो सकता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुबह जल्दी उठना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस समय वातावरण में प्रदूषण कम होता है और हवा अधिक स्वच्छ होती है। ताजी हवा में सांस लेने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जो मस्तिष्क और अन्य अंगों के लिए आवश्यक होती है। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और सोचने की क्षमता बेहतर होती है। यही कारण है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वे अपने कार्यों में अधिक कुशल और सक्रिय पाए जाते हैं।

ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संबंध हमारी जैविक घड़ी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर एक प्राकृतिक लय के अनुसार कार्य करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। जब हम इस लय के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो हमारा शरीर संतुलित रहता है और हम अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना इस लय को बाधित करता है, जिससे शरीर में थकान, आलस्य और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत, यदि हम समय पर सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित और ऊर्जावान बने रहते हैं।

भारतीय संस्कृति में इस समय को आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। जब व्यक्ति इस ऊर्जा के साथ जुड़ता है, तो उसका मन शांत और आत्मा शुद्ध होती है। जप, ध्यान और प्रार्थना इस समय करने से अधिक प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि उस समय मन पूरी तरह से एकाग्र होता है। यही कारण है कि साधु-संत और योगी इस समय को अपनी साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। यदि इस समय घर की खिड़कियां खोल दी जाएं और ताजी हवा को अंदर आने दिया जाए, तो घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। दीपक जलाना या मंत्रों का उच्चारण करना भी इस ऊर्जा को और अधिक प्रभावी बना देता है। इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है, जो पूरे दिन तक बना रहता है।

दादी-नानी की यह सलाह केवल स्वास्थ्य या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और सफलता से भी जुड़ी हुई है। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है, जो व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से समय पर उठता है, तो उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और उसके जीवन में एक संतुलन बना रहता है। यह अनुशासन ही उसे जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।

आज के आधुनिक युग में, जहां लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक चुनौती बन गया है। मोबाइल, इंटरनेट और मनोरंजन के साधनों ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इसी कारण से यह आदत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम इस शांत समय को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। यह समय हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है, जो दिन के अन्य समय में संभव नहीं होता।

ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होती है, तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। व्यक्ति अधिक सक्रिय, उत्साही और प्रेरित महसूस करता है। धीरे-धीरे यह आदत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और उसे दूसरों से अलग पहचान देती है। यह केवल एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक जीवनशैली बन जाती है, जो उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है।

हालांकि, इस आदत को अपनाने के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। अचानक बहुत जल्दी उठने की कोशिश करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या को बदलें। सबसे पहले हमें अपने सोने का समय ठीक करना चाहिए, ताकि शरीर को पर्याप्त आराम मिल सके। जब शरीर पूरी तरह से विश्राम करता है, तभी सुबह जल्दी उठना वास्तव में लाभकारी होता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और संतुलित जीवनशैली का हिस्सा है। यह आदत हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। दादी-नानी की यह सीख कि "जो सूरज से पहले उठता है, वही आगे बढ़ता है" वास्तव में जीवन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत सही समय और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है और यही सच्ची सफलता का मार्ग बन जाता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# डिंडोली में 'आयरन सिंडिकेट' का भंडाफोड़: 60 टन चोरी की टीएमटी रॉड बरामद, एसओजी की रेड में चार दबोचे

सूरत। शहर के तेजी से बढ़ते निर्माण कारोबार के बीच चोरी के एक संगठित रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। Surat City Special Operations Group ने डिंडोली इलाके में सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 60 टन चोरी की टीएमटी रॉड के साथ चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई न केवल मात्रा के लिहाज से बड़ी है, बल्कि इससे उस संगठित नेटवर्क की झलक भी मिलती है जो ट्रांसपोर्ट चेन के भीतर सेंध लगाकर करोड़ों का माल गायब कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, भाग्यलक्ष्मी सोसाइटी के पास की गई इस रेड में कुल 59,910 किलोग्राम लोहे की रॉड बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 32.95 लाख रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही एक ट्रेलर (करीब 33 लाख रुपये), एक चार पहिया वाहन (लगभग 5 लाख रुपये), मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई। कुल मिलाकर करीब 71.52 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस के कब्जे में आई है। यह बरामदगी बताती है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर माल खपाने की क्षमता रखता था।

गिरफ्तार आरोपियों में भेराराम रेखाराम जाखड़ और निम्बाराम बाबूलाल जाखड़—दोनों बाड़मेर (राजस्थान) के निवासी—ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के रूप में काम करते थे। इनके साथ डिंडोली में रहने वाले प्रदीप सदाबृज त्रिपाठी (मूल निवासी उत्तर प्रदेश) और प्रदीप किशनलाल शर्मा (मूल निवासी राजस्थान) को भी दबोचा गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी मिलकर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल में हेरफेर कर बड़ी मात्रा में रॉड निकाल लेते थे और फिर उसे सस्ते दामों पर स्थानीय बाजार में खपाने की कोशिश करते थे।



जांच में जो तरीका सामने आया है, वह बेहद सुनियोजित है। ट्रक में लदी खेप के कागज सही रहते थे, लेकिन रास्ते में या गंतव्य से पहले तय स्थानों पर माल का एक हिस्सा उतार लिया जाता था। इसके बाद शेष माल को नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता, जिससे पहली नजर में किसी तरह की कमी पकड़ में न आए। इस तरह छोटे-छोटे हिस्सों में की गई चोरी समय के साथ बड़ी मात्रा में बदल जाती थी। पुलिस का मानना है कि इस तरीके से कई बार वारदातें की गई होंगी।

इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, यह 'लाइव रेड' थी—यानी जैसे ही गिरोह माल खपाने की कोशिश में सक्रिय हुआ, टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। Rajdeepsinh Nakum ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह इनपुट-आधारित थी और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ना इस बात का सबूत है कि पुलिस ने लंबे समय से इस नेटवर्क पर नजर रखी हुई थी।

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के पीछे दो कथित मास्टरमाइंड—जीतू और राजन तिवारी—हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इनके पकड़े जाने के बाद इस रैकेट के और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट चेन के अन्य लोग या बिचौलिए शामिल हो सकते हैं।

मामले का एक अहम पहलू चोरी के माल की 'डिमांड साइड' है—यानी यह रॉड किन-किन खरीदारों तक पहुंचाई जा रही थी। निर्माण क्षेत्र में टीएमटी रॉड की लगातार मांग रहती है, और कम कीमत पर मिलने वाला माल कई बार बिना पर्याप्त जांच के खरीद लिया जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई व्यापारी, बिल्डर या सप्लायर इस चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चारों आरोपियों के खिलाफ डिंडोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिमांड लेकर उनसे गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि पिछले मामलों, अन्य सहयोगियों और सप्लाई चैन की पूरी कड़ी को सामने लाया जा सके। यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस गिरोह का संबंध अन्य शहरों या राज्यों में सक्रिय नेटवर्क से तो नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण सामग्री की चोरी का यह पैटर्न नया नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ पकड़ी गई खेप इस बात का संकेत है कि निगरानी और सत्यापन तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों, गोदाम संचालकों और खरीदारों के बीच बेहतर समन्वय और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे अपराधों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

फिलहाल, सूरत पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे न केवल करोड़ों रुपये के नुकसान को रोका गया है, बल्कि उन संगठित गिरोहों को भी स्पष्ट संदेश गया है जो सप्लाई चेन में सेंध लगाकर अवैध कमाई करते हैं। आने वाले दिनों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की जांच इस पूरे मामले को और स्पष्ट करेगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि 'आयरन सिंडिकेट' की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए किन-किन स्तरों पर कार्रवाई की जरूरत है।

# तेल के तूफान और वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार पर दबाव, HSBC ने घटाई रेटिंग

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तेजी से बदलते संकेतों के बीच अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था HSBC ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपना रुख और अधिक सतर्क कर लिया है। लगातार दूसरी बार रेटिंग में कटौती करते हुए HSBC ने इंडियन इक्विटीज को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' कर दिया है। इससे पहले 31 मार्च को ही फर्म ने इसे 'ओवरवेट' से 'न्यूट्रल' किया था। यानी एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी गिरावट है, जो बाजार के प्रति बढ़ती चिंताओं को साफ तौर पर दर्शाती है।

इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल बताया जा रहा है। Brent Crude की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है और हाल के महीनों में इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इससे न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि कंपनियों के मुनाफे पर भी सीधा असर पड़ता है। HSBC की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। NSE Nifty और BSE Sensex जैसे प्रमुख सूचकांकों में हालिया गिरावट ने निवेशकों की चिंता को और गहरा कर दिया है। निफ्टी जहां करीब 6.7 प्रतिशत तक गिर चुका है, वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 7.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट भारत को उन प्रमुख बाजारों की सूची में शामिल कर रही है, जहां हाल के समय में प्रदर्शन कमजोर रहा है। विदेशी निवेशकों की भूमिका भी इस गिरावट में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा करीब 18.5 अरब डॉलर की शुद्ध बिकवाली की गई है। यह आंकड़ा न केवल निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है, बल्कि रुपये पर भी दबाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। जब विदेशी निवेशक लगातार पूंजी निकालते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पर बाजार की तरलता और स्थिरता पर पड़ता है।

HSBC ने अपनी रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया है—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। रिपोर्ट के अनुसार, AI के बढ़ते उपयोग से आईटी सेवाओं के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है। भारत का आईटी सेक्टर लंबे समय से वैश्विक सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन नई तकनीकों के चलते इस सेक्टर की आय में अनिश्चितता बढ़ सकती है। यह स्थिति निवेशकों के लिए एक नया जोखिम पैदा करती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। HSBC का अनुमान है कि जून और सितंबर तिमाही के दौरान ऊर्जा आपूर्ति में तंगी बनी रह सकती है। इसका सीधा असर कंपनियों की लागत और मुनाफे पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस कारण भारत की अर्निंग ग्रोथ में करीब 1.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन बड़े पैमाने पर यह बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

बाजार के मूल्यांकन (Valuation) को लेकर भी HSBC ने चिंता जताई है। हालिया गिरावट के बावजूद, यदि कंपनियों की कमाई के अनुमान और घटते हैं, तो मौजूदा वैल्यूएशन भी महंगे साबित हो सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि कीमतों में और गिरावट की संभावना बनी रहती है।

विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशी निवेशकों का रुख और तकनीकी बदलाव—ये सभी कारक मिलकर बाजार की दिशा तय करेंगे। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने और सोच-समझकर निवेश करने का है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट अवसर भी बन सकती है। जब बाजार दबाव में होता है, तब मजबूत कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य और सही रणनीति की आवश्यकता होती है।

# 2,800 करोड़ का दांव: भारत में ई-कॉमर्स की रफ्तार बढ़ाने उतरा अमेजन, एआई और कर्मचारियों पर बड़ा फोकस

नई दिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए Amazon India ने 2,800 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह निवेश सिर्फ एक कारोबारी विस्तार नहीं, बल्कि देश में ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी ने साफ किया है कि यह राशि ऑपरेशंस नेटवर्क के विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटलीकरण और कर्मचारियों के समग्र कल्याण पर खर्च की जाएगी।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल उपभोक्ता बाजारों में शामिल हो चुका है। कंपनी की दीर्घकालिक योजना के तहत 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, और मौजूदा 2,800 करोड़ उसी बड़े विज़न की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अमेजन भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देख रहा है।

कंपनी के मुताबिक, इस निवेश का बड़ा हिस्सा एआई-आधारित टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में लगाया जाएगा। इससे सप्लाई चेन को अधिक स्मार्ट, तेज और कुशल बनाया जाएगा। ग्राहकों के ऑर्डर को समझने, डिमांड का अनुमान लगाने और डिलीवरी को समयबद्ध बनाने में एआई अहम भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में ग्राहक कुछ ही मिनटों या घंटों में अपने उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे, जो ई-कॉमर्स अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है।

लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। कंपनी अपने फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्टेशन हब और लास्ट-माइल डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत करेगी। इसका सीधा फायदा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा, जहां अब तक तेज डिलीवरी एक चुनौती बनी हुई थी। यह विस्तार न केवल ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और विक्रेताओं को भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेगा।

क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी अमेजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी की सेवा 'Amazon Now' पहले ही प्रमुख शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और अब इसे और विस्तार देने की योजना है। वर्तमान में 300 से अधिक माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर के जरिए यह सेवा ग्राहकों तक तेज डिलीवरी सुनिश्चित कर रही है। नए निवेश के बाद यह नेटवर्क और व्यापक होगा, जिससे मिनटों में डिलीवरी का सपना और करीब आएगा।

कर्मचारी कल्याण इस निवेश का एक अहम स्तंभ है। अमेजन ने 'प्रोजेक्ट आश्रय' के तहत अपने कर्मचारियों और उनसे जुड़े समुदायों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें अब और विस्तार दिया जाएगा। कंपनी मेडिकल और दुर्घटना बीमा को मजबूत करेगी, साथ ही हजारों कर्मचारियों और 2 लाख से अधिक सामुदायिक सदस्यों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल केवल कॉर्पोरेट जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक स्थायी और समावेशी विकास मॉडल की ओर इशारा करती है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेजन ने भारत में इतना बड़ा निवेश किया हो। वर्ष 2025 में भी कंपनी ने 2,000 करोड़ का निवेश किया था, जिसके तहत देशभर में 17 फुलफिलमेंट सेंटर, 6 सॉर्टेशन सेंटर और 75 लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन स्थापित किए गए थे। इन प्रयासों ने पहले ही डिलीवरी समय को कम करने और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अमेजन का यह नया निवेश भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को और तेज करेगा। इससे अन्य कंपनियां भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी। नतीजतन, पूरे सेक्टर में नवाचार, रोजगार सृजन और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा।

हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लॉजिस्टिक्स लागत, अंतिम मील की डिलीवरी की जटिलताएं और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाना अब भी कठिन कार्य हैं। इसके अलावा, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता गोपनीयता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन अमेजन का यह निवेश यह संकेत देता है कि कंपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कुल मिलाकर, 2,800 करोड़ का यह निवेश केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल और ई-कॉमर्स भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में इसका असर न केवल ग्राहकों के अनुभव पर पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी विकास पर भी गहराई से दिखाई देगा।

# पश्चिम रेलवे चलाएगी गांधीधाम-मालदा टाउन–गांधीधाम समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम–मालदा टाउन–गांधीधाम के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

**ट्रेन संख्या 09463/09464 गांधीधाम-मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल**

▸▸ ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम-मालदा टाउन समर स्पेशल दिनांक 25 अप्रैल 2026 (शनिवार) को गांधीधाम से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सोमवार को 09:10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी।

▸▸ इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09464 मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल दिनांक 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को मालदा टाउन से 17:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन बुधवार को 15:30 बजे गांधीधाम पहुंचेगी।

▸▸ यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में सामाखियाली, राधनपुर, भीलड़ी, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना, किउल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बड़हरवा और न्यू फरक्का स्टेशनों पर रुकेगी।

▸▸ इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम – मालदा टाउन समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 24 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

▸▸ ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

# पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09435/09436 साबरमती–आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (विशेष किराये पर) चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 29 अप्रैल 2026 को साबरमती से 22:55 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 14:30 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09436 आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 01 मई 2026 को आसनसोल से 16:15 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, इडगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा तथा धनबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 24 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

# जग्गी हत्याकांड में बड़ा मोड़: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को अंतरिम राहत, उम्रकैद पर लगी रोक

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने रामअवतार जग्गी हत्याकांड में एक अहम मोड़ आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने पूर्व विधायक Amit Jogi को अंतरिम राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले ने न केवल मामले की दिशा बदल दी है, बल्कि कानूनी बहस को भी नए सिरे से तेज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि फिलहाल सजा के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी और जोगी को 23 अप्रैल तक सरेंडर करने के निर्देश को भी स्थगित किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने Central Bureau of Investigation से जवाब तलब किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपील और दोषसिद्धि की प्रक्रिया में किन आधारों पर निर्णय लिए गए थे। यह आदेश इस बात का संकेत है कि अदालत मामले के हर पहलू को गहराई से परखना चाहती है।

सुनवाई के दौरान जोगी पक्ष के वरिष्ठ वकीलों ने दो अहम बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, सीबीआई को अपील की अनुमति देने के आदेश की वैधता, और दूसरा, हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि का आधार। बचाव पक्ष का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में जोगी को बरी किया था, ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला कई कानूनी सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक स्तर पर राहत देना उचित समझा।

यह मामला लगभग दो दशक पुराना है, जिसकी जड़ें 4 जून 2003 की उस घटना से जुड़ी हैं, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता Ramavatar Jaggi की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह घटना एक बड़ा झटका मानी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच राज्य पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसने विस्तृत जांच के बाद अमित जोगी समेत कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान 31 मई 2007 को ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला उस समय काफी चर्चा में रहा था। हालांकि, बाद में सीबीआई की अपील पर Chhattisgarh High Court ने मामले की दोबारा सुनवाई की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को भी दोषी करार दे दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 23 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें अब अंतरिम राहत मिली है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह राहत अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सुरक्षा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम सुनवाई तक आरोपी को तुरंत सजा का सामना न करना पड़े। अदालत अब सीबीआई के जवाब और दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के आधार पर आगे का फैसला करेगी।

# सोना वायदा में 642 रुपये और चांदी वायदा में 6083 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा में 93 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 256639.12 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26905.15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 229733.96 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2629.7 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17271.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 152051 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152543 रुपये और नीचे में 151451 रुपये पर पहुंचकर, 152657 रुपये के पिछले बंद के सामने 642 रुपये या 0.42 फीसदी घटकर 152015 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 461 रुपये या 0.38 फीसदी औंधकर 121424 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 56 रुपये या 0.37 फीसदी घटकर 15221 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 150701 रुपये के भाव पर खूलकर, 151080 रुपये के दिन के उच्च और 150063 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 618 रुपये या 0.41 फीसदी गिरकर 150597 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 150652 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151211 रुपये और नीचे में 150128 रुपये पर पहुंचकर, 151390 रुपये के पिछले बंद के सामने 643 रुपये या 0.42 फीसदी घटकर 150747 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 242501 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 244730 रुपये और नीचे में 239600 रुपये पर पहुंचकर, 248364 रुपये के पिछले बंद के सामने 6083 रुपये या 2.45 फीसदी घटकर 242281 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 5937 रुपये या 2.37 फीसदी लुढ़ककर 244407 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 5935 रुपये या 2.37 फीसदी गिरकर 244479 रुपये प्रति किलो हुआ।



मेटल वर्ग में 4297.52 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 5.55 रुपये या 0.43 फीसदी गिरकर 1277.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 75 पैसे या 0.21 फीसदी की नरमी के साथ 348.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 35 पैसे या 0.09 फीसदी की नरमी के साथ 372.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी घटकर 196.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4926.47 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8799 रुपये के भाव पर खूलकर, 9026 रुपये के दिन के उच्च और 8791 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 93 रुपये या 1.07 फीसदी की तेजी के संग 8816 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 93 रुपये या 1.07 फीसदी की तेजी के संग 8817 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 255.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 257.3 रुपये और नीचे में 254.8 रुपये पर पहुंचकर, 255.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 70 पैसे या 0.27 फीसदी बढ़कर 256.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 80 पैसे या 0.31 फीसदी चढ़कर 256.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

▸▸ **कमोडिटी वायदाओं में 26905.15 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 229733.96 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 17271.17 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार**

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 998 रुपये पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी टूटकर 999.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7620.69 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9650.47 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3520.21 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 394.38 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 11.07 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 366.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3845.08 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1065.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.93 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9828 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61202 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28919 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 392994 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65679 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9185 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 26520 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 100568 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14635 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 34546 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 20.9 रुपये की बढ़त के साथ 663 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.2 रुपये की गिरावट के साथ 0.5 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 167 रुपये की गिरावट के साथ 817 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1941 रुपये की गिरावट के साथ 705 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.99 रुपये की गिरावट के साथ 2.84 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 97 पैसे के सुधार के साथ 3.3 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 5.2 रुपये की गिरावट के साथ 367.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.75 रुपये की गिरावट के साथ 1.05 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 32.5 रुपये की बढ़त के साथ 400.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 68.5 रुपये की बढ़त के साथ 288.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की गिरावट के साथ 0.97 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 18 पैसे की नरमी के साथ 0.01

# भारत की आर्थिक ताकत पर सूरत से बड़ा संदेश: इंडस्ट्री ही विकास की असली धुरी, वैश्विक मंच पर बढ़ी देश की अहमियत

सूरत। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की स्थिति को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत संदेश सूरत से सामने आया, जहां Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री Mansukh Mandaviya ने देश की आर्थिक दिशा और उद्योगों की भूमिका पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भारत का बाजार केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जिसके चलते कोई भी देश भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास यात्रा में उद्योगपतियों और व्यापारियों की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि आजादी से पहले भी और उसके बाद भी देश की प्रगति में व्यापारिक वर्ग ने अहम योगदान दिया है। "जो लोग संपत्ति का निर्माण करते हैं, वे राष्ट्र निर्माण के सच्चे भागीदार हैं और उनका सम्मान होना चाहिए," इस बात को दोहराते हुए उन्होंने उद्योग जगत को सरकार का सहयोगी बताया, न कि केवल एक आर्थिक इकाई।

मंत्री ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत लगातार 7 से 8 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है, जो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे सुधारों और योजनाओं का परिणाम है। सरकार संतुलित विकास मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें रोजगार सृजन, व्यापार विस्तार और आय वृद्धि तीनों को समान महत्व दिया जा रहा है।

कर प्रणाली में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि Goods and Services Tax लागू होने के बाद कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दरों में कमी के बावजूद सरकार को हर महीने करीब 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और कर सुधारों की सफलता बताया।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे व्यापक निवेश को देश की प्रगति का इंजन बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार करीब 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसके तहत देश में प्रतिदिन औसतन 31 किलोमीटर हाईवे और 15 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, पिछले दस वर्षों में लगभग 100 नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही उद्योगों को विस्तार देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की शक्ति देता है।

इस संवाद कार्यक्रम में केवल सरकारी दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि उद्योग जगत की समस्याओं और सुझावों को भी प्रमुखता से सामने रखा गया। उद्योगपतियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और मंत्री के सामने व्यावहारिक समाधान की मांग रखी। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उद्योग हितैषी नीति और जीएसटी रिफंड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया।

टेक्सटाइल उद्योग, जो सूरत की पहचान है, उससे जुड़े प्रतिनिधियों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। इस पर मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार और उद्योग मिलकर इस दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

कार्यक्रम में शहर के विकास से जुड़े मुद्दे भी उठे। मल्टी-गेम स्टेडियम और रो-रो फेरी सेवा जैसी मांगों के साथ सूरत को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इन प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय का भरोसा दिलाया, जिससे सूरत को एक वैश्विक व्यापारिक हब के रूप में और मजबूती मिल सके।

खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जहां सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं लेबर लॉ को लेकर जागरूकता बढ़ाने के सुझाव पर उन्होंने वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

इस पूरे कार्यक्रम ने एक बात साफ कर दी कि सरकार और उद्योग के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, देश की आर्थिक प्रगति उतनी ही तेज होगी। मंच पर मौजूद विभिन्न पदाधिकारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस संवाद को सकारात्मक और उपयोगी बताया।

कुल मिलाकर, सूरत में आयोजित यह बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक दिशा और वैश्विक भूमिका पर एक गंभीर विमर्श के रूप में सामने आई। यहां से निकला संदेश साफ है कि उद्योग ही देश की तरक्की की रीढ़ हैं और यदि सरकार व उद्योग मिलकर आगे बढ़ें, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भी मजबूत स्थान हासिल कर सकता है।

# महिला आरक्षण पर टकराव तेज, सहमति की मांग के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर

शिमला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जहां एक ओर इसे लोकतांत्रिक सुधार का बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेज़ी ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति नहीं बल्कि व्यापक सहमति बननी चाहिए, ताकि देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक राजनीतिक अधिकार मिल सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान समय में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48 प्रतिशत होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी महज 14-15 प्रतिशत तक सीमित है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक बड़ा असंतुलन दर्शाता है। डेज़ी ठाकुर ने सितंबर 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे लंबे समय से लंबित मांग के रूप में देखा जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा पाई, जिससे महिलाओं के अधिकारों को लेकर भ्रम और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है, जबकि उन्हें संगठन और नेतृत्व के स्तर पर पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते। उनके अनुसार, यदि कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर होती, तो इस मुद्दे पर स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाती। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं—जैसे वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा—महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो रहा है। इस पूरे विवाद के बीच भाजपा महिला मोर्चा ने "जन आक्रोश महिला पदयात्रा" निकालने की घोषणा की है। डेज़ी ठाकुर के अनुसार, यह अभियान केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और सम्मान के प्रति जागरूक करना भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में यह पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जाएगा और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में चुनावी राजनीति का एक केंद्रीय विषय बन सकता है। यह मुद्दा सीधे तौर पर देश की बड़ी मतदाता आबादी को प्रभावित करता है, इसलिए सभी दल इसे अपने-अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर सत्तापक्ष इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन और समयसीमा को लेकर सवाल उठा रहा है।

# हिमाचल कांग्रेस में सियासी संग्राम: नियुक्तियों के विरोध में भूख हड़ताल, दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर उठी असंतोष की लहर अब खुली बगावत का रूप लेती दिख रही है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष पद पर हाल ही में की गई नियुक्ति के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौहान ने शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह विरोध केवल एक पद की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से सुलग रहे क्षेत्रीय असंतुलन, गुटबाज़ी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला रहा है।

भूख हड़ताल पर बैठे प्रदीप चौहान ने आरोप लगाया कि हालिया संगठनात्मक फेरबदल में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा है और फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले का गिरिपार क्षेत्र, जो जनसंख्या और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उनके मुताबिक, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जिन नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनमें अधिकांश पांवटा साहिब क्षेत्र से आते हैं, जबकि गिरिपार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व के नाम पर लगभग शून्य स्थान मिला है।

चौहान ने यह भी कहा कि संगठन में ऐसे लोगों को पद दिए जा रहे हैं जिनका अतीत दल-बदल से जुड़ा रहा है, जबकि वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की नियुक्तियां न केवल संगठन की जड़ों को कमजोर करती हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी तोड़ती हैं। उन्होंने इसे "कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय" बताते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो सकती है।

भूख हड़ताल के दौरान चौहान ने प्रदेश नेतृत्व के सामने स्पष्ट मांग रखी है कि पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए और संगठन में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद उत्पन्न न हों। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और दिल्ली जाकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर भी धरना देंगे, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठ सके।

इस विरोध ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाज़ी को उजागर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल स्थानीय स्तर का नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक असंतोष का संकेत है जो संगठन के भीतर लंबे समय से पनप रहा है। आगामी संगठनात्मक पुनर्गठन और भविष्य के चुनावों को देखते हुए इस तरह के विरोध पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं।

शिमला में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई स्थानीय कार्यकर्ता भी चौहान के समर्थन में सामने आए हैं। उनका कहना है कि संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ सीमित लोगों तक सिमटकर रह गई है, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की आवाज दब रही है।

# यमदूत बना ट्रक: ड्रमंडगंज घाटी में भीषण हादसा, 11 की मौत, बोलेरो में जिंदा जले 8 लोग

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले की ड्रमंडगंज घाटी बुधवार की रात उस वक्त चीखों, आग और तबाही का भयावह मंजर बन गई, जब एक बेकाबू ट्रक ने नेशनल हाईवे-135 पर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि 11 जिंदगियां पलभर में खत्म हो गईं। रात करीब 8 बजे हुए इस भीषण हादसे में एक बोलेरो सवार 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक कार चालक और ट्रक के ड्राइवर-खलासी की भी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए ऐसा जख्म बन गया है, जो जिंदगी भर नहीं भर पाएगा।

घटना के समय घाटी में सामान्य आवाजाही जारी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा एक भारी ट्रक जैसे ही ड्रमंडगंज घाटी के ढलान पर पहुंचा, उसका ब्रेक अचानक फेल हो गया। घाटी का तीखा ढलान और ट्रक की तेज रफ्तार इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गए। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन ट्रक पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। देखते ही देखते वह सामने चल रहे वाहनों के लिए मौत बन गया।

सबसे पहले ट्रक ने एक कंटेनर को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन हादसे की असली भयावहता इसके बाद सामने आई। कंटेनर से टकराने के बाद भी ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई और उसने आगे चल रही बोलेरो को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के साथ ही बोलेरो में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला बन गई।

बोलेरो में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन के दरवाजे जाम हो गए थे और आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका। अंदर बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलकर राख हो गया और उसमें सवार 8 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इस हादसे की त्रासदी और भी गहरी हो जाती है।

हादसे की चपेट में आई एक अन्य कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक जय प्रकाश (28), जो सोनभद्र का रहने वाला था, इस टक्कर में बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक और खलासी भी इस भीषण दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच गई।

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे, लेकिन आग और धुएं के कारण कोई भी करीब नहीं जा पा रहा था। कुछ लोगों ने पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाफी साबित हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब 60 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोलेरो और कार पूरी तरह जल चुके थे और अंदर मौजूद लोगों के शव बुरी तरह झुलस चुके थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए डीएनए परीक्षण की भी जरूरत पड़ सकती है।

इस हादसे के कारण वाराणसी-रीवा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। करीब चार घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर और सड़क साफ कर आंशिक रूप से यातायात बहाल किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में इस तरह के हादसे अक्सर वाहन की तकनीकी खराबी और लापरवाही के कारण होते हैं। खासकर ब्रेक सिस्टम की नियमित जांच न होना और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं ऐसे हादसों को जन्म देती हैं। ड्रमंडगंज घाटी पहले भी कई हादसों के लिए बदनाम रही है, जहां तेज ढलान और मोड़ दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं।

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के उन सवालों को सामने लाता है, जिन पर अक्सर हादसे के बाद ही चर्चा होती है। क्या ट्रकों की फिटनेस की सही जांच हो रही है? क्या घाटी क्षेत्रों में गति नियंत्रण के नियमों का पालन किया जा रहा है? क्या ड्राइवरों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये सभी सवाल इस त्रासदी के बाद और भी अहम हो जाते हैं।

ड्रमंडगंज की यह रात अब सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक ऐसा दर्द बन चुकी है, जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खो दिया। जलती हुई बोलेरो में फंसे लोगों की चीखें और सड़क पर पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहे थे कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है।

# जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा: यूपी में भूमि विवाद निपटाने के लिए विशेष टीमें, सीएम योगी के सख्त निर्देश

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े भूमि विवादों और अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण में अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर प्राथमिकता के आधार पर मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इनमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, अवैध कब्जे, पुलिस कार्रवाई में देरी और चिकित्सा सहायता से जुड़े थे। हर एक मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर भूमि विवादों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी शिकायतें मिलें, वहां तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की जाए और कब्जा हटाने की कार्रवाई बिना देरी के की जाए। साथ ही, इस तरह के मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सके।

उन्होंने यह भी कहा कि भूमि विवाद केवल राजस्व विभाग का मामला नहीं है, बल्कि इसमें पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त टीम बनाएं, जो न केवल विवादों की पहचान करे बल्कि उनका सत्यापन कर त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करे। यह मॉडल खासतौर पर उन जिलों में लागू किया जाएगा, जहां भूमि विवादों की संख्या अधिक है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में समर्पित विशेष टीमें बनाई जाएं, जो केवल भूमि विवादों के निस्तारण पर ध्यान दें। इन टीमों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे प्राथमिकता के आधार पर मामलों का समाधान करें और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाएं। इस व्यवस्था से न केवल विवादों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

पुलिस से जुड़े मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर शिकायत के प्रति संवेदनशील और निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो, इसके लिए हर मामले की जांच तथ्यों के आधार पर की जाए और कार्रवाई में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या पक्षपात की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

राज्य में भूमि विवाद लंबे समय से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। कई बार ये विवाद छोटे झगड़ों से शुरू होकर गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस 'विशेष टीम मॉडल' को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो इससे न केवल विवादों का तेजी से समाधान होगा, बल्कि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ेगा।

जनता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। कई फरियादियों ने अपनी जमीन पर कब्जे और वर्षों से चल रहे विवादों की शिकायत रखी, जिन पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जमीन से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह पहल जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वास्तव में लोगों को इससे राहत मिलती है या नहीं।

# डिजिटल दौर में 'मूल हिन्दी' पर संकट: सरकारी वेबसाइटों से हटे असली स्वरूप पर उठा बड़ा विवाद

लखनऊ। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल गवर्नेंस के बीच अब भाषा को लेकर एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी वेबसाइटों पर हिन्दी के मूल स्वरूप के गायब होने और उसकी जगह मशीनी अनुवाद आधारित सिस्टम लागू किए जाने के आरोपों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब मुंबई निवासी प्रवीण कुमार जैन ने इस संबंध में एक विस्तृत शिकायत पत्र सीधे केंद्र सरकार और संसदीय राजभाषा समिति को भेजकर इसे न केवल भाषाई बल्कि संवैधानिक मुद्दा करार दिया। मुंबई के बोरीवली पूर्व क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण जैन द्वारा भेजे गए इस पत्र में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की अधिकांश आधिकारिक वेबसाइटों पर अब अंग्रेजी ही प्राथमिक और मूल भाषा के रूप में बनी हुई है, जबकि हिन्दी को केवल एक अनुवादित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोप है कि 'भाषिणी' और 'अनुवादिनी' जैसे मशीनी अनुवाद टूल्स के जरिए हिन्दी सामग्री दिखाई जा रही है, जिससे न केवल भाषा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि हिन्दी की संवैधानिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। यह मामला सीधे संविधान से जुड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठाया गया है कि जब हिन्दी राजभाषा है, तो उसे मूल भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि किसी तकनीकी अनुवाद का परिणाम बनाकर। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2 जुलाई 2008 को जारी राष्ट्रपति के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी सरकारी वेबसाइटों को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में बनाए रखना अनिवार्य होगा। मौजूदा स्थिति को इस आदेश के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है।

प्रवीण जैन ने अपने पत्र में यह भी तर्क दिया है कि मशीनी अनुवाद टूल्स जैसे 'भाषिणी' और 'अनुवादिनी' का उद्देश्य अन्य भारतीय भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना हो सकता है, लेकिन हिन्दी जैसी राजभाषा के लिए इनका उपयोग प्रतिस्थापन के रूप में करना न केवल अनुचित है बल्कि यह भाषा के स्तर को भी गिराता है। उन्होंने कहा कि इन टूल्स द्वारा किया गया अनुवाद अक्सर संदर्भहीन, त्रुटिपूर्ण और समझ से परे होता है, जिससे आम नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी को समझना मुश्किल हो जाता है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी असमानता और भाषाई भेदभाव से भी जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 'भाषिणी' प्लेटफॉर्म का इंटरफेस मुख्यतः अंग्रेजी में है, और कई जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। यहां तक कहा गया है कि डिजिटल युग में यह स्थिति अंग्रेजी को अप्रत्यक्ष रूप से थोपने की नीति को दर्शाती है। इस पूरे मामले ने राजभाषा नीति के क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा हर साल राजभाषा के प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी दफ्तरों, बैंकों और ऑनलाइन सेवाओं में हिन्दी का प्रयोग सीमित ही रह गया है। कई जगहों पर द्विभाषी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है, जबकि व्यवहार में अंग्रेजी का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। रिपोर्टों में 100 प्रतिशत अनुपालन दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। प्रवीण जैन ने इस मुद्दे को केवल शिकायत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार के सामने स्पष्ट मांगें भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी वेबसाइटों पर हिन्दी के मूल संस्करण को तत्काल बहाल किया जाए और मशीनी अनुवाद टूल्स का उपयोग हिन्दी के लिए नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए किया जाए। साथ ही, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म—चाहे वे वेबसाइट हों, मोबाइल ऐप हों या रजिस्ट्रेशन सिस्टम—पूरी तरह द्विभाषी बनाए जाएं, ताकि हर नागरिक को अपनी भाषा में सेवाएं मिल सकें।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की है कि राजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हिन्दी की स्थिति धीरे-धीरे और कमजोर हो सकती है, जिससे संविधान की भावना को ठेस पहुंचेगी।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही हैं।